



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 2 मई, 2008/12 वैशाख, 1930

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 1 मई, 2008

संख्या एल०एल०आर०-डी०(६)-८/२००८-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30-04-2008 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्यांक 6) को वर्ष 2008 के अधिनियम संख्यांक 6 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

जे० एन० बारोवालिया,
प्रधान सचिव ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2008**धाराओं का क्रम****धाराएँ :**

1. संक्षिप्त नाम ।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए 29,65,37,48,362 रुपये की और राशि प्राधिकृत करना ।
3. विनियोग ।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2008

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 30 अप्रैल, 2008 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2001-02 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2008 है । संक्षिप्त नाम ।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग 29,65,37,48,362 (उन्नीस अरब, पैंसठ करोड़ सैंतीस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ बासठ रुपये केवल) है, वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी । हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए 29,65,37,48,362 रुपये की और राशि प्राधिकृत करना ।
3. इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2001-2002 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी । विनियोग ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1 मांग संख्या	2 सेवाएं और प्रयोजन	3 निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत रुपये	संचित निधि पर प्रभारित रुपये	जोड़ रुपये
1	विधान सभा (राजस्व)	—	3,25,830	3,25,830
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन (राजस्व)	24,33,85,750	70,228	24,34,55,978
	(पूंजी)	1,09,000	—	1,09,000
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (राजस्व)	—	30,000	30,000
10	लोक निर्माण-भवन (राजस्व)	47,92,98,155	—	47,92,98,155
11	कृषि (पूंजी)	15,44,77,527	—	15,44,77,527
13	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण (राजस्व)	16,76,57,611	—	16,76,57,611
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (पूंजी)	3,81,08,138	—	3,81,08,138
16	वन और वन्य जीवन (राजस्व)	—	1	1
17	सड़कें और पुल (राजस्व)	8,54,78,899	—	8,54,78,899
19	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-पोषाहार (पूंजी)	18,98,000	—	18,98,000
23	जल और विद्युत विकास (पूंजी)	48,62,99,000	—	48,62,99,000
24	मुद्रण एवं लेखन (राजस्व)	56,90,206	—	56,90,206
	(पूंजी)	7,99,702	—	7,99,702

1	2	3		
		रुपये	रुपये	रुपये
28	जलापूर्ति, सफाई, आवास (राजस्व)	1,03,18,21,406	—	1,03,18,21,406
	और नगर विकास (पूंजी)	16,03,77,724	50	16,03,77,774
29	वित्त (पूंजी)	92,73,978	26,52,50,16,888	26,53,42,90,866
30	विविध सामान्य सेवायें (पूंजी)	9,84,787	—	9,84,787
31	जन जातीय विकास (राजस्व)	26,26,45,482	—	26,26,45,482
	जोड़ (राजस्व)	2,27,59,77,509	4,26,059	2,27,64,03,568
	(पूंजी)	85,23,27,856	26,52,50,16,938	27,37,73,44,794
	(कुल जोड़)	3,12,83,05,365	26,52,54,42,997	29,65,37,48,362

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT***THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (No. 3) ACT, 2008****ARRANGEMENT OF SECTIONS***Sections :*

1. Short title.
2. Authorisation of a further sum of Rs. 29,65,37,48,362 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year, 2001-2002.
3. Appropriation.

THE SCHEDULE

Act No. 6 of 2008

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (No. 3) ACT, 2008

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 30TH APRIL, 2008)

AN

ACT

to provide for the authorisation of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial year 2001-2002 in excess of the amount authorized or granted for those services for that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Short title.
Appropriation (No. 3) Act, 2008.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 29,65,37,48,362 (Twenty Nine hundred Sixty Five crore, Thirty Seven lakhs, Fourty Eight thousand Three Hundred Sixty Two rupees only) shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year 2001-2002 in excess of the amount authorised or granted for those services for that year.

Authorisation of a further sum of Rs. 29,65,37,48,362 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year 2001-2002.

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year 2001-2002.

Appropriation.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1	2		3		
			Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly Rs.	Charged on the Consolidated Fund Rs.	Total Rs.
1	Vidhan Sabha	(Revenue)	—	3,25,830	3,25,830
5	Land Revenue and District Administration	(Revenue) (Capital)	24,33,85,750 1,09,000	70,228 —	24,34,55,978 1,09,000
9	Health and Family Welfare	(Revenue)	—	30,000	30,000
10	Public Works— Buildings	(Revenue)	47,92,98,155	—	47,92,98,155
11	Agriculture	(Capital)	15,44,77,527	—	15,44,77,527
13	Irrigation and Flood Control	(Revenue)	16,76,57,611	—	16,76,57,611
15	Planning and Backward Area Sub-Plan	(Capital)	3,81,08,138	—	3,81,08,138
16	Forest and Wild Life	(Revenue)	—	1	1
17	Roads and Bridges	(Revenue)	8,54,78,899	—	8,54,78,899
19	Social Security and Welfare (Including Nutrition)	(Capital)	18,98,000	—	18,98,000
23	Water and Power Development	(Capital)	48,62,99,000	—	48,62,99,000

1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
24	Stationery and Printing (Revenue)	56,90,206	—	56,90,206
	(Capital)	7,99,702	—	7,99,702
28	Water Supply, (Revenue)	1,03,18,21,406	—	1,03,18,21,406
	Sanitation Housing and (Capital)	16,03,77,724	50	16,03,77,774
	Urban Development			
29	Finance (Capital)	92,73,978	26,52,50,16,888	26,53,42,90,866
30	Miscellaneous General (Capital)	9,84,787	—	9,84,787
	Services			
31	Tribal Development (Revenue)	26,26,45,482	—	26,26,45,482
	Total (Revenue)	2,27,59,77,509	4,26,059	2,27,64,03,568
	(Capital)	85,23,27,856	26,52,50,16,938	27,37,73,44,794
	Grand Total	3,12,83,05,365	26,52,54,42,997	29,65,37,48,362

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला—171 002, 1 मई, 2008

संख्या एल0एल0आर0—डी0(6)—9 / 2008—लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30-04-2008 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्यांक 7) को वर्ष 2008 के अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

जे0 एन0 बारोवालिया,
प्रधान सचिव ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2008

धाराओं का क्रम

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम ।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए 32,95,75,77,342 रुपये की और राशि प्राधिकृत करना ।
3. विनियोग ।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2008

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 30 अप्रैल, 2008 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2002-03 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2008 है । संक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग 32,95,75,77,342 (बत्तीस अरब, पच्चास करोड़ पच्चाहत्तर लाख सतहत्तर हजार तीन सौ बियालीस रुपये केवल) है, वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी । हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए 32,95,75,77,342 रुपये की और राशि प्राधिकृत करना ।

3. इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी । विनियोग ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1 मांग संख्या	2 सेवाएं और प्रयोजन	3 निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत रुपये	संचित निधि पर प्रभारित रुपये	जोड़ रुपये
3	न्याय प्रशासन और निर्वाचन (राजस्व)	—	5,42,459	5,42,459
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन (राजस्व)	2,44,39,530	—	2,44,39,530
6	आबकारी और कराधान (राजस्व)	53,29,561	—	53,29,561
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन (राजस्व)	9,35,70,390	—	9,35,70,390
	(पूंजी)	50,00,000	—	50,00,000
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (राजस्व)	1,75,93,209	1	1,75,93,210
10	लोक निर्माण-भवन (राजस्व)	65,20,26,020	—	65,20,26,020
12	उद्यान (पूंजी)	75,84,896	—	75,84,896
13	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण (राजस्व)	29,75,51,103	—	29,75,51,103
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र (पूंजी)	5,97,79,890	—	5,97,79,890
	उप-योजना			
17	सड़कें व पुल (राजस्व)	50,93,73,201	—	50,93,73,201
18	आपूर्ति उद्योग और खनिज (पूंजी)	5,497	—	5,497
20	ग्रामीण विकास (राजस्व)	46,887	—	46,887

1	2	3		
		रुपये	रुपये	रुपये
23	जल और विद्युत विकास (राजस्व) (पूंजी)	4,72,49,433 1,04,41,46,000	— —	4,72,49,433 1,04,41,46,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण (राजस्व)	91,65,232	—	91,65,232
28	जलापूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास (राजस्व) (पूंजी)	90,56,55,191 49,52,387	— —	90,56,55,191 49,52,387
29	वित्त (पूंजी)	—	29,11,03,61,016	29,11,03,61,016
31	जनजातीय विकास (राजस्व) (पूंजी)	13,88,57,441 2,43,47,998	— —	13,88,57,441 2,43,47,998
	जोड़ (राजस्व)	2,70,08,57,198	5,42,460	2,70,13,99,658
	(पूंजी)	1,14,58,16,668	29,11,03,61,016	30,25,61,77,684
	कुल जोड़	3,84,66,73,866	29,11,09,03,476	32,95,75,77,342

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (No. 4) ACT, 2008**ARRANGEMENT OF SECTIONS***Sections :*

1. Short title.
2. Authorisation of a further sum of Rs. 32,95,75,77,342 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year 2002-2003.
3. Appropriation.

THE SCHEDULE

Act No. 7 of 2008.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (No. 4) ACT, 2008

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 30TH APRIL, 2008)

AN

ACT

to provide for the authorisation of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial year 2002-2003 in excess of the amount authorized or granted for those services for that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Short title.
Appropriation (No. 4) Act, 2008.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 32,95,75,77,342 (Thirty Two hundred Ninety Five crore, Seventy five lakhs, Seventy Seven thousand Three hundred Fourty Two rupees only) shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year 2002-2003 in excess of the amount authorised or granted for those services for that year.

Authorisation of a further sum of Rs. 32,95,75,77,342 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year 2002-2003.

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year 2002-2003.

Appropriation.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1 No. of De- mand	2 Services and purposes	3		
		Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly Rs.	Charged on the Consolidated Fund Rs.	Total Rs.
3	Administration of Justice (Revenue) and Election	—	5,42,459	5,42,459
5	Land Revenue and (Revenue) District Administration	2,44,39,530	—	2,44,39,530
6	Excise and Taxation (Revenue)	53,29,561	—	53,29,561
7	Police and Allied (Revenue) Organisations (Capital)	9,35,70,390 50,00,000	— —	9,35,70,390 50,00,000
9	Health and Family (Revenue) Welfare	1,75,93,209	1	1,75,93,210
10	Public Works— (Revenue) Buildings	65,20,26,020	—	65,20,26,020
12	Horticulture (Capital)	75,84,896	—	75,84,896
13	Irrigation and Flood (Revenue) Control	29,75,51,103	—	29,75,51,103
15	Planning and Backward (Capital) Area Sub-Plan	5,97,79,890	—	5,97,79,890
17	Roads and Bridges (Revenue)	50,93,73,201	—	50,93,73,201
18	Supplies, Industries and (Capital) Minerals	5,497	—	5,497

1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
20	Rural Development (Revenue)	46,887	—	46,887
23	Water and Power Development (Revenue)	4,72,49,433	—	4,72,49,433
	(Capital)	1,04,41,46,000	—	1,04,41,46,000
27	Labour, Employment and Training (Revenue)	91,65,232	—	91,65,232
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development (Revenue)	90,56,55,191	—	90,56,55,191
	(Capital)	49,52,387	—	49,52,387
29	Finance (Capital)	—	29,11,03,61,016	29,11,03,61,016
31	Tribal Development (Revenue)	13,88,57,441	—	13,88,57,441
	(Capital)	2,43,47,998	—	2,43,47,998
	Total (Revenue)	2,70,08,57,198	5,42,460	2,70,13,99,658
	(Capital)	1,14,58,16,668	29,11,03,61,016	30,25,61,77,684
	Grand Total	3,84,66,73,866	29,11,09,03,476	32,95,75,77,342

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अप्रैल, 2008

संख्या एल० एल० आर०-डी०(6)-3/2008-लेज.- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28-4-2008 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्यांक 4) को वर्ष 2008 के अधिनियम संख्यांक 5 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
जे० एन० बारोवालिया,
प्रधान सचिव।

2008 का अधिनियम संख्यांक 5**हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2008**

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 28 अप्रैल, 2008 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम.— इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2008 है।

2. धारा 2 का संशोधन.— हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (2003 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (क) में, “या समान या समरूप वेतनमानों में राज्य के भीतर अनुज्ञेय ऐसे अन्य भत्ते (अखिल भारतीय सेवा नियमों के अधीन से अन्यथा),” शब्दों, कोष्ठकों और चिन्हों का लोप किया जाएगा।

3. धारा 3 का प्रतिस्थापन.— मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“**3. वेतन.**—भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश अथवा निर्णय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य में न्यायिक अधिकारियों को अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट वेतनमान संदत्त किए जाएंगे और ऐसे अधिकारियों के भत्तों की दरें और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।”

4. धारा 4 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 4 की उन-धारा (1) में, “नियम बना सकेगी” शब्दों से पूर्व “भूतलक्षी प्रभाव से” शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

—
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 5 of 2008.

THE HIMACHAL PRADESH JUDICIAL OFFICERS (PAY, ALLOWANCES AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT ACT, 2008

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 28TH APRIL, 2008)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, allowances and Conditions of Service) Act, 2003 (Act No. 13 of 2003).

BE it enacted by the legislative assembly of Himachal Pradesh in the fifty-ninth year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Amendment Act, 2008.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Act, 2003 (13 of 2003) (hereinafter referred to as the “principal Act”), in clause (a), the words, brackets and signs “admissible within the State (other than under All India Service Rules), in identical or similar scale of pay,” shall be deleted.

3. Substitution of section 3 .—For section 3 of the principal Act, the following shall be substituted, namely :—

“3. Salaries.—Notwithstanding anything contained in any rules made under any other law for the time being in force, regulating the pay, allowances and other conditions of service,

or any order or judgment passed by any court, the Judicial Officers in the State shall be paid the pay scales as specified in the Schedule and the rates of allowances and other conditions of service of such Officers shall be such as may be prescribed.”.

4. *Amendment of section 4.*—In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), after the words “make rules”, the words “with retrospective effect” shall be inserted.